भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3505
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मदुरै में एम्स

†3505. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ख) मदुरै एम्स परियोजना के लिए आवंटित/उपयोग किए गए कुल बजट का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या धनराशि के वितरण में कोई विलम्ब हो रहा है जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) मदुरै एम्स परियोजना में देरी के मुख्य कारण क्या हैं तथा इनका समाधान किस प्रकार किया जा रहा है;
(ङ) क्या उक्त परियोजना के निर्माण और संचालन में और अधिक विलम्ब से बचने के लिए कोई आकस्मिक योजना हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या केन्द्र सरकार ने मदुरै एम्स परियोजना की प्रगति के बारे में राज्य सरकार और जनता को नियमित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत 2021.51 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मदुरै की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में, चरण-I का 26% कार्य पूरा हो चुका है। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौते के अनुसार परियोजना के पूरा होने की लक्षित तारीख अक्टूबर, 2026 है। आज की स्थिति के अनुसार, एम्स मदुरै के निर्माण के लिए 239.27 करोड़ रुपये निर्गत किए जा चुके हैं। परियोजना क्रियाकलापों के लिए निधि के वितरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) से (च) : एम्स मदुरै की आधारशिला वर्ष 2019 में रखी गई थी, हालांकि परियोजना के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सौंपी गई थी। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के माध्यम से परियोजना के लिए निधि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था और मार्च, 2021 में जापान सरकार और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 150 बिस्तरों वाले संक्रामक रोग ब्लॉक और कुछ अन्य अनुवृद्धि को शामिल करने के कारण परियोजना लागत को भी संशोधित किया गया था। संस्थान और मंत्रालय के स्तर पर परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के उचित कार्यान्वयन की निगरानी और सुविधा के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

******